स्वास्थ्य ढांचे के लिए कितना मुश्किल

स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बेहतर नहीं है। इसका पता तब चलता है जब वर्कर नर्सों की संख्या देखी जाए। वर्कर नर्सों और डॉक्टरों का अनुपात वहां भी एक और एक का ही है। वर्कर नर्सों से मतलब उन नर्सों से है, जो पंजीकृत होने के साथ–साथ सक्रिय भी हों।

नवीन शाह।।

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) की ओर से जारी की गई हालिया स्टडी रिपोर्ट देश में डॉक्टरों और नर्सों तथा सहायक स्वास्थ्यकर्मियों के बीच कम अनुपात का जायजा लेते हुए बताती है कि कोरोना महामारी की चुनौतियों से जूझना इस कमजोर स्वास्थ्य ढांचे के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। भारत में नर्सों और डॉक्टरों का अनुपात 1.7:1 है यानी हर एक डॉक्टर पर 1.7 नर्स। यह अनुपात कितना कम है, इसका अंदाजा इस तथ्य से मिलता है कि ओईसीडी (ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनमिक को–ऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट) देशों का औसत अनुपात 4रू1 है यानी हर एक डॉक्टर पर चार नर्स।

अपने यहां तस्वीर तब और चिंताजनक हो जाती है, जब इसमें क्वॉलिटी का फैक्टर जोड़ दिया जाता है। क्वॉलिफिकेशन का ख्याल रखते हुए देखा जाए तो यह अनुपात 1:1. 3 बैठता है यानी 1.3 डॉक्टरों पर एक नर्स। डॉक्टर से भी कम नर्स। बहरहाल, औसत अनुपात के ये आंकड़े भी जमीनी हकीकत का ठोस अंदाजा नहीं देते। अलग–अलग राज्यों में एकदम अलग–अलग स्थिति है। कुछ राज्यों में डॉक्टर ज्यादा हैं तो कुछ अन्य राज्यों में नर्सों की संख्या अधिक है। उदाहरण के लिए, एक तरफ पंजाब और दिल्ली जैसे राज्य हैं जहां नर्सों और डॉक्टरों का अनुपात क्रमशरू 6.4 और एक एवं 4.5 और एक का है तो दूसरी तरफ बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां प्रति डॉक्टर एक नर्स का भी अनुपात नहीं बैठता।

केरल में सबसे ज्यादा नर्सें हैं। लेकिन वहां भी हॉस्पिटलों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बेहतर नहीं है। इसका पता तब चलता है जब वर्कर नर्सों की संख्या देखी जाए। वर्कर नर्सों और डॉक्टरों का अनुपात वहां भी एक और एक का ही है। वर्कर नर्सों से मतलब उन नर्सों से है, जो पंजीकृत होने के साथ–साथ सक्रिय भी हों। दिलचस्प तथ्य यह है कि कई राज्य जो डॉक्टर और नर्स अनुपात के आंकड़ों के लिहाज से काफी अच्छी स्थिति में नजर आते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की क्वॉलिटी के मामले में उतना अच्छा मानक नहीं दर्शा पाते। उदाहरण के लिए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य।

यहां डॉक्टर और नर्सों का अनुपात अगर अच्छा नजर आता है तो उसकी वजह नर्सों की पर्याप्त संख्या नहीं बल्कि डॉक्टरों की कम संख्या है। इन राज्यों में प्रति दस हजार आबादी पर एक डॉक्टर हैं। नर्सों का हाल भी खास अच्छा नहीं है। देश में प्रति 670 लोगों पर एक नर्स का अनुपात बैठता है जबकि डब्ल्यूएचओ का मानदंड प्रति 300 लोगों पर एक नर्स का है। इस संदर्भ में देखें तो स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के लिहाज से अपने देश में चर्चा हमेशा डॉक्टरों की कमी की ही होती है। उस कमी को पूरा करना भी जरूरी है, लेकिन समझना होगा कि नर्सों और सहायक स्वास्थ्यकर्मियों का अनुपात ठीक किए बिना स्वास्थ्य सेवाओं का ऊंचा स्तर सुनिश्चित करना मुमकिन नहीं है।

प्रार्थना

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

बीरबल ने कहा, "जी महाराज! हाथियों का राजा गजेन्द्र जब एक मगरमच्छ द्वारा पकड़ लिया गया था, जो उसे मारना चाहता था, तब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने प्रार्थना सुन ली और वे गजेन्द्र को बचाने के लिए आये थे।" अकबर ने कहा, "गजेन्द्र की रक्षा के लिए भगवान खुद क्यों आये। वह अपने सेवकों को भी भेज सकते थे। उनके पास तो कई सारे सेवक होंगे?" बीरबल ने कहा, "मैं कुछ ही दिनों में इस सवाल का जवाब दे दूंगा।" राजकुमार अक्सर अपने एक सेवक के साथ शाम को सैर के लिए जाते थे। बीरबल ने चतुराई से उस सेवक से दोस्ती कर ली और उसे किसी को भी बताने के लिए मना किया वे दोस्त थे। फिर वह मोम का एक पुतला लेकर आया, जो बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखता था।

संपादकीय

सामने खड़ी चुनौती

भारत किस तरह से रूस, अमेरिका, इटली, स्पेन सहित बाकी देशों के साथ अपने संबंधों को लेकर एक सामूहिक रणनीति बनाता है, यह देखने लायक बात होगी। अपने पिछले जी–20 संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अफगानिस्तान में एक सर्वमान्य सरकार होनी चाहिए। और अगर तालिबान को मानवीय मदद चाहिए तो उसे एक जिम्मेदार सहयोगी के रूप में काम करना होगा। जिस तरह से तालिबान सत्ता में आए और जिस तरह का शासन वे चला रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय उसे देखते हुए तालिबान को मान्यता देने को लेकर आश्वस्त नहीं है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने यह भी समस्या है कि जितनी इसमें देर लग रही है, उतनी ही वहां की हालत खराब होती जा रही है। भारत का जोर इस पर है कि जिस तरह की मान्यता या वित्तीय मदद आज तालिबान को चाहिए, उसे काफी सोच–विचार कर देना होगा, जिससे अफगानिस्तान के भविष्य में अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपना योगदान पूरी तरह दे पाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो तालिबान को मान्यता भी मिल जाएगी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो बदलाव चाहता है, वे भी नहीं होंगे। सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने कई देशों से मिलकर अफगानिस्तान की बात उठाई है, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान में जिस तरह से खाद्य और मानवीय समस्या बढ़ती नजर आ रही है, वह बहुत जल्द यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने चुनौती खड़ी करेगी।

फगानिस्तान की जमीनी हकीकत न सिर्फ बड़ी तेजी से बदली है, बल्कि ऐसी दिशा में चली गई है कि इसे अभी काबू में ना किया गया, तो आने वाले समय में, खासकर सर्दियों में हालत और खराब होने की उम्मीद है।

भारत का दिलचस्प रोल

हर्ष वी. पंत।।

अफगानिस्तान को लेकर पश्चिमी देशों, पाकिस्तान, चीन और रूस को उम्मीद थी कि जिस तरह की जीत तालिबान को मिली है, वहां स्थिरता काफी जल्दी आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वहां जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ती जा रही है। वहां मानवीय संकट पैदा हो रहा है, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है। इसलिए दुनिया और खासकर अफगानिस्तान के पड़ोसी देश सोच रहे हैं कि इसका समाधान क्या हो। इस पर रूस और ईरान अपनी बैठक कर चुके। भारत भी अपना समिट करने वाला है।

अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत न सिर्फ बड़ी तेजी से बदली है, बल्कि ऐसी दिशा में चली गई है कि इसे अभी काबू में ना किया गया, तो आने वाले समय में, खासकर सर्दियों में हालत और खराब होने की उम्मीद है। अगर वहां मानवीय संकट बढ़ता है तो न सिर्फ पड़ोसी देशों की परेशानी बढ़ेगी, बल्कि पश्चिमी देशों पर भी काफी प्रेशर आएगा। रोम में हुए जी–20 और बाकी सम्मेलनों को इसी लिहाज से समझना होगा। हर कोई चाहता है कि उसका तालिबान में स्टेटस बढ़े, लेकिन इसमें किसी को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। वहां जैसी मानव आपदा दिख रही है, उसके चलते आतंकवाद और

शरणार्थियों की समस्या बढ़ेगी। इसे काबू में करने के लिए रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक मीटिंग हुई थी। फिर मॉस्को में मीटिंग हुई, जिसमें भारत भी शामिल हुआ। 27 अक्टूबर को तेहरान में मीटिंग हुई और इसी महीने भारत में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग होनी है। अब भारत दो चीजें कर रहा है। एक तो वह बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। दूसरे, वह इस मसले पर खुद की मीटिंग बुला रहा है। यह काफी रोचक है, क्योंकि पहले भारत कहता था कि हम दूर बैठकर बस हालात देखेंगे।

भारत के रूस या ईरान से बदलते रिश्तों का भी इस मामले में प्रभाव पड़ रहा है। शुरू में हमने देखा कि रूस ने चीन और पाकिस्तान को मजबूती से सपोर्ट किया। फिर हालात बदले तो रूस को लगा कि भारत के साथ मेलजोल बहुत जरूरी है। वहीं ईरान की शिया–सुन्नी वाली समस्या काफी जहरीली है। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमलों पर ईरान ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उसने 27 तारीख वाली मीटिंग में भारत को न्योता नहीं दिया था। माना जा सकता है कि क्वाड समिट को लेकर ईरान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। उधर, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। नब्बे के दशक से तुलना करें तो आज दोनों देशों के रिश्ते बिलकुल अलग हैं। पहले अमेरिका तालिबान समर्थक रुख दिखा रहा था, लेकिन पिछले डेढ़ महीने में वह भारत के रुख का समर्थन कर रहा है। यह नया डिवेलपमेंट है और इसका प्रभाव नई पॉलिसी पर पड़ रहा है।

पिछले कुछ समय से भारत का यही मानना रहा है कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता मिलनी चाहिए। हालांकि, वह यह मदद तालिबान के जरिये नहीं करना चाहता है। उसका तर्क है कि मानवीय सहायता देने के लिए हमारे पास स्वायत्त तंत्र होना चाहिए। भारत ने यह बात पहले भी कही है कि तालिबान को योजना बनानी होगी और बताना होगा कि राहत सामग्री का वितरण वह कैसे करेगा। जहां तक मानवीय सहायता का सवाल है, वह तालिबान को न देकर इंटरनैशनल एजेंसियों को दी जाए और तालिबान इन्हें बांटने के लिए एजेंसियों को रास्ता दे।

सूडोकु नवताल-5406

सरल

6					7			
		8	2				7	5
	4			3				6
	7	1			2		5	
8				4				3
	2		8			9	6	
2				8			3	
4	3				9	8		
			3					9

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5405 का हल

7	4	6	9	1	5	8	3	2
1	5	2	8	3	7	4	6	9
9	3	8	2	6	4	7	1	5
8	6	4	7	9	1	5	2	3
5	2	7	3	4	6	9	8	1
3	9	1	5	8	2	6	7	4
2	7	9	1	5	8	3	4	6
6	1	5	4	7	3	2	9	8
4	8	3	6	2	9	1	5	7

अपना ब्लॉग

सारे देश इसके लिए पूरी तरह तैयार

मोहन। भारत ने इस मुद्दे को फ्रेम किया है और सारे देश इसके लिए तैयार हैं। कोई नहीं चाहता कि इसे तालिबान के जरिए इसे बांटा जाए क्योंकि इससे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो तालिबान को लगेगा कि उसे मान्यता मिल रही है। दूसरे, वह राहत सामग्री का इस्तेमाल अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए करेगा, न कि इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाएगा। आने वाली बैठकों में तय हो सकता है कि किस तरह से अंतरराष्ट्रीय समुदाय मदद देगा। हालांकि, अभी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह का बिखराव है। पाकिस्तान के साथ चीन है और पश्चिमी देश एक तरफ हैं। ऐसे में यह संभावना कम हो जाती है कि इसे लेकर कोई वैश्विक सहमति बनेगी। अमेरिका आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान में ठिकाना चाहता है। वहीं, पाकिस्तान ने उसके साथ ऐसे किसी समझौते से इनकार किया है। पाकिस्तान बार–बार कह रहा है कि अफगानिस्तान की मदद होनी चाहिए और तालिबान को वैधता मिलनी चाहिए, जिसे मानने वाले देश बहुत कम हैं।